

accordance with the claim made on the label. No physical injury or damage could have been caused by the use of these tablets since the content of active ingredient in the tablets was up to the specification.

(d) and (e) After discovery of the defect no achromycin injections were used in the hospital. However 51,000 tablets of ferrous are shown to have been issued in to the hospital record after the 'spotting' and had been noticed. Since ferrous sulphate is a fast moving item in the hospitals, it is surmised that these tablets may have been issued before the discovery of 'spotting' but were brought on record subsequently.

12 NOON

POINT OF ORDER RE CALLING ATTENTION NOTICE TAKEN UP ON MONDAY, THE 27TH APRIL, 1970

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सम्भाषति : क्या आर्डर पेपर के मुताल्लिक है कुछ ?

श्री राजनारायण : हां। मैं आप और आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से एक व्यवस्था प्रश्न पर विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसी व्यवस्था न हो इस सदन के बाहर इस सरकार की पुलिस डंडा चलाये और सदन के भीतर इस सरकार की तिकड़म हमारे ऊपर डंडा चलाये। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस नियम की तह में काम हो रहा है कि मुझे अभी तक इस सदन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कल हमारे ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव पर घर मंत्री का बयान हुआ, आपने इजाजत दी कि राजनारायण अब उस पर अपनी बात कहे। तो ध्यान आकर्षण का हमारा प्रस्ताव था, हम उनके वक्तव्य के बाद तुरन्त पूछते और फिर मैं अपनी बात कहता। यही आखिर है तो मैं इन पजेशन आफ द हाऊस हूँ, इसके बाद उस पर कुछ बारीकी से नियमों की, कानूनों की, और अपनी जो यहां पर एक व्यवस्था ली थी, तो आपकी उस व्यवस्था पर तर्क-वितर्क प्रणाली चल गई। तो क्या उस तर्क-वितर्क प्रणाली में हमारा ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव विलकुल छुप जायेगा, दब जायेगा, आयेगा

नहीं— मैं जानना चाहता हूँ। और अब आपके द्वारा इस सदन और सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा यदि छः तारीख की घटना पर बिना इस सदन में चर्चा करके कोई और कार्यवाही आगे बढ़ने दूंगा। तो आपसे कहना चाहता हूँ : यदि 6 अप्रैल की घटना जिसमें 2,000 आदमियों पर मार पड़ी, एक आदमी की जान गई है, हमारी टांग तोड़ी गई है, जार्ज फर्नन्डेज एम० पी० और आल इंडिया एस० एस० पी० पार्टी के जेनरल सेक्रेटरी कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमये लोक सभा के सदस्य पीटे गये हैं, अर्जुन सिंह भदोरिया जिनको दो दिन तक पेशाब पाखाना नहीं हुआ, उस सब की चर्चा यहां न हो और सदन की कार्यवाही चलती रहे यह हमारे लिये लज्जा का विषय होगा, हम लोगों के लिये डूब मरने का विषय होगा। आप वह मार्ग हमें बतायें जिससे संसदीय प्रणाली में मैं अपनी बातों को इस सदन में पेश करूं। कानून की बारीकी में और सरकार की तिकड़म में इस सदन को बांधा नहीं जा सकता और जब तक मैं जिंदा हूँ, बांधने नहीं दूंगा। यह मेरा आपसे निवेदन है, फिर आपकी जो भी व्यवस्था हो। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं इस सदन का सदस्य हूँ। कल इस सदन में बैठते बैठते हमारे पांवों में सूजन आ गई...

श्री सम्भाषति : आपसे मैंने कहा आप बैठ कर बात करिये।

श्री राजनारायण : आपके कहने से क्या होगा ? हमारी भावना भी तो है। हम बैठ जाते हैं। हम मजबूर हो जायेंगे, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहेंगे। हमारे पांवों में सूजन आ गई कल...

श्री सम्भाषति : मैं तो पहले ही कह दिया था आप खड़े होकर न बोलें।

श्री राजनारायण : हमारी भावना के साथ संविधान के साथ, जनतंत्र के साथ, देश की जनता के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। वह मुझे बाध्य करता है मैं सदन में आऊं

वरना मुझे अस्पताल में रहना चाहिये । डॉक्टरों की सलाह थी कि मैं न जाऊँ, लेकिन मैं आया हूँ कर्तव्य से बाध्य होकर । आप मुझे बताये कि कल जहाँ से विषय उठा, आज उस विषय पर चर्चा न हो और दूसरे विषय ले लिये जायें । उपसभापति से मैंने कल कहा था कि मैं चेयरमैन साहब की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने एक साधु परम्परा चलायी ; उन्होंने ध्यान आकर्षण भी मान लिया, उन्होंने मिनिस्टर के स्टेटेमेंट देने के हक को भी मान लिया । जो प्रणाली उन्होंने चलायी उस प्रणाली के द्वारा उन्होंने यह भी कह दिया कि घर मंत्री के बयान पर अब सदन...

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : आन अ पौइन्ट आफ आर्डर ।

श्री राजनारायण : यह जो नाजुक लेडी है, मैं आपके द्वारा उनको बतलाना चाहता हूँ, इस देश की आजादी में उन्होंने कितना हिस्सा बटाया है । हमने तो इस देश की आजादी के लिये कुछ किया है । उस आजादी को खत्म नहीं करना होगा । इसलिये लीगल क्विबलिंग की, अनाप शनाप की बातें होना...

(Interruptions)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप कौन हैं रोकने वाले । चेयरमैन साहब आप रोक सकते हैं । मैं तो उनकी भावना की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं केवल इतना कह रही थी कि क्या यह पौइन्ट आफ आर्डर है । वह कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले ? आपको कोई अधिकार नहीं । मुझे बिठाने की आज्ञा चेयर देगा ।

(Interruptions)

श्री राजनारायण : हमने अपनी भावनाएं आज प्रकट कर दीं । मेरे ऊपर जो बीती, क्यों बीती, उसके बारे में कहने के लिये इन तमाम कालिंग अटेन्शन, स्टेटेमेंट, आदि के अतिरिक्त भी हज़ार खता हूँ, नियम की तह में, कि आपसे इजाजत लूँ कि आप मुझे मौक़ा दें कि हमारे ऊपर जो बीती उस पर अपना स्पष्टीकरण करें । यह भी हमको अपने नियम की तह में एक अधिकार मिला है । इसलिये मैं सभी बातों को आपके सामने प्रकट कर दे

रहा हूँ और इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस तेजस्विता के साथ, कि मरने तक आप उठवा कर फिकवा देंगे, ठीक, वरना जो नियम हैं, जो साधु परम्परा है, वही हमको कर्तव्य से प्रेरित करती है । मैं आपसे अनुनय विनय करके निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम इस दिल्ली में 6 तारीख अप्रैल को जो राष्ट्रीय सप्ताह का प्रथम दिवस था उसमें जो चोट पहुंचाई गई समाजवाद और जनतंत्र पर उसकी चर्चा हो...

श्री सभापति : सुन लिया ।

श्री राजनारायण : और सुन लीजिए । आज कालिंग अटेन्शन आपने दिया है नक्सलाइट्स के बारे में, यह कालिंग अटेन्शन अधूरा हो जायेगा अगर 6 अप्रैल की घटना पर पहले चर्चा हुए बिना इस कालिंग अटेन्शन पर चर्चा होती है तो, क्योंकि 6 अप्रैल की घटना पैदा करती है नक्सलाइट को । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र मोहन धारिया और चन्द्रशेखर भी सुनें, कि ऐसी ही घटनाएं नक्सलाइट्स को पैदा करती हैं, पैदा करेंगी । कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता अगर साधु पद्धति से जनतंत्रीय पद्धति से हमारी बातों पर आप ध्यान नहीं देते तो ।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण : हम बैठे हैं ।

श्री सभापति : यह जो प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया है यह एजेन्डे के किसी आइटम के ऊपर तो आता नहीं है मगर मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुझे यह मालूम हुआ कि श्री राजनारायण जी के चोट आई है और यह इंसीडेन्ट हुआ तो मुझे बेहद दुःख हुआ । श्री राजनारायण जी मानेंगे कि मुझे उनके चोट लगने का बहुत ही दुःख है और इस इंसीडेन्ट के होने का भी मुझे दुःख है । मगर मुझे कायदे से चलना है और यह मेरी एक जिम्मेदारी है ।

जब मेरे पास कालिंग अटेन्शन मोशन का नोटिस आया तो मैंने फौरन उसको मंजूर कर लिया । जब मेरे पास शार्ट डिचूरेशन डिस्कशन का नोटिस आया तो मैंने फौरन उसको

[श्री सभापति]

मंजूर कर लिया। जिस वक्त यह सवाल आया कि हाउस में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर डिस्कशन हो, तो उसके लिए भी मैं राजी हो गया कि आप इस सिलसिले में इस बात को भी कह सकते हैं।

अब सवाल यह है कि कल जब कार्लिंग अटेंशन मोशन आया तो उस वक्त मैंने उसको हाउस के सामने रख दिया और उसको मंजूर कर लिया और शार्ट डचरेशन डिस्कशन को भी मंजूर कर लिया। तो अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : इस पर डिस्कशन हो।

श्री सभापति : तब उसके बाद यह मालूम हुआ कि शार्ट डचरेशन डिस्कशन चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है और यहां पर शार्ट डचरेशन डिस्कशन हो। उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद तब यह सवाल पैदा हुआ कि शार्ट डचरेशन डिस्कशन के क्या माने हैं और फिर बहुत सी बात हुई।

आज मेरे पास एक जनरल मोशन का नोटिस आया है। अब मैं इस को देखूंगा कि कल क्या हुआ है और मैं रिकार्ड पढ़ रहा हूं। इस वक्त जो दूसरा नोटिस मोशन का आया है, उसको मैं कंसीडर करूंगा और उस के बारे में सोचूंगा। मैं यहां पर एकदम कैसे कह दूं एक ही बात का ख्याल करके और जो बातें मुझे सोचनी हैं उन सब को छोड़ दूं। (Interruption) डिप्टी चेयरमैन साहब ने कल कहा था कि जो लीडर साहबान चेयरमैन साहब से कुछ कहना चाहते हैं वे उन से कहें।

विपक्ष के नेता (श्री श्यामनन्दन मिश्र) : इस बात को मैं दुबस्त कर देना चाहता हूं। सुझाव यह था कि चेयरमैन साहब लीडर साहबान को आमंत्रित करेंगे। लीडर साहबान चेयरमैन साहब से मिलेंगे यह बात नहीं हुई।

(Interruptions)

श्री ए० पी० जैन (उत्तर प्रदेश) : यह बात सही नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह देखता हूं कि आप वाइस चेयरमैन बन गये हैं। आप को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये।

श्री ए० पी० जैन : जैसे आपको बोलने का हक है, उसी तरह से मुझे भी बोलने का हक है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम चेयर से बात कर रहे हैं, आप से बात नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : इन सब बातों को देखने के लिए मुझे वक्त चाहियेगा और धीरे देखे मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता हूं जब तक कि मैं इस चीज पर अच्छी तौर से गौर न कर लूं। डिस्कशन मैंने एलाउ किया है लेकिन इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। इस बारे में जो भी लीडरान साहब मुझ से मिलना चाहते हैं वे आकर मिल सकते हैं क्योंकि मैं अभी उठ कर चला जाऊंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कल यहां पर जो कुछ हुआ है उसको आप देखें।

श्री सभापति : आप क्या यह नहीं चाहते हैं कि कल जो कुछ यहां पर हुआ है कम से कम उस रिकार्ड को तो मैं पढ़ सकूं और उसके बाद अपनी राय कायम कर सकूं ? मैं रिकार्ड पढ़ कर आपको बतला दूंगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिये और आज जो काम है वह मेरी राय में लिया जाना चाहिये और वह चलना चाहिये।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आपने विशेष अनुकम्पा नहीं की। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि कल मैं सदन के पजेशन में था। कल घर मंत्री जी ने हमारे कार्लिंग अटेंशन के नोटिस पर उठकर जवाब दिया और इस तरह से अपने कर्तव्य

का पालन किया। उसके तत्काल बाद जो कार्लिंग अटेंशन नोटिस था उस पर हम अपनी बात पूछते। डा० जाकिर हुसैन साहब ने यहां पर एक साधु बुद्धि की परम्परा चलाई कि चूंकि इस सदन में एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता है, अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है इसलिए उन्होंने कार्लिंग अटेंशन नोटिस की परिधि को इतना बढ़ा दिया ताकि सब बातों का समावेश उसमें आ जाय। वही परम्परा यहां पर चल रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे कार्लिंग अटेंशन नोटिस का क्या हुआ, वह कहाँ चला गया। घर मंत्री के वक्तव्य के बाद डिप्टी चेयरमैन कहते हैं कि मैं उठूं। आप इस सारे रिकार्ड को देख लें। मैं जिस समय अपना प्रश्न करने के लिए उठा ही था तो अपोजीशन की तरफ से कई तरह की व्यवस्थाओं के प्रश्न आ गये और उन व्यवस्थाओं के प्रश्नों को डिप्टी चेयरमैन साहब सुलझा नहीं पाये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा वह प्रश्न पूछने का अधिकार समाप्त हो गया क्या? यह तो हमारा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि आप कानून के मास्टर हैं। जस्टिस डिलैड इज जस्टिस डिनाइड। जिस तात्कालिकता और अविलम्बनीयता को लेकर विरोधी पक्ष ने घर मंत्री की निन्दा करनी चाही कि घर मंत्री ने स्वयं आकर 6 तारीख की घटना के संबंध में सरकार की ओर से सफाई पेश क्यों नहीं की, क्या वह तात्कालिकता और अविलम्बनीयता नहीं रह गई है?

श्री समापति : यही सब कहने के लिए तो मैंने मौका दिया था। शार्ट ड्यूरेषन डिसकशन के माने हर सदस्य समझता है और इसीलिए मैंने यह मौका दिया था। अगर उस मौके का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं?

श्री राजनारायण : आप जो कुछ कह रहे हैं वह एक प्रकार से डिप्टी चेयरमैन के संबंध में अविश्वास की बात कर रहे हैं। परोक्ष

रूप में आप यह कह रहे हैं कि अगर डिप्टी चेयरमैन साहब सदन में व्यवस्था नहीं बना सक रहे हैं तो उस में चेयरमैन क्या करें। उसका मतलब तो यह हुआ कि डिप्टी चेयरमैन नालायक है। हमारा हक है कि मैं कार्लिंग अटेंशन के संबंध में खड़ा होकर बोलूं। डिप्टी चेयरमैन साहब मुझे पुकारते हैं और उसके बाद सदन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उठाई जाती हैं। फिर भी डिप्टी चेयरमैन साहब सदन को इस रूप में नहीं ला पाये कि मैं अपनी बात कह सकूं। इन सब बातों को देखते हुए और जितनी बातें आप ने कहीं उनको देखते हुए डिप्टी चेयरमैन की कर्तव्य बुद्धि में हीनता आई है। इसीलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम बातों की रोशनी में हम को बोलने के लिए मौका दें। सत्य की जय होगी या जो जय होगी वही सत्य हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि आप सत्य की जय करें। आप सत्यमेव जयते पढ़ते हैं, जयते सत्यमेव नहीं पढ़ते।

चेयरमैन साहब, हमारी प्रार्थना पर आप गौर करेंगे और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप को हक है कि 6 तारीख की घटना पर हम को अपना स्पष्टीकरण करने का मौका दें। मैं बारबार इस सदन में कह रहा हूं कि आप हमें अपनी बात कहने का मौका दें और उसके बाद सदन जो चाहे वह फैसला करे। हमारा जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हजारों की तादाद में दूर-दूर प्रदेशों से स्त्री और पुरुष आये हुए थे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में कोई व्यवस्था दें।

श्री समापति : मेरा यही जवाब है जो मैं अभी कह चुका हूं। वह जो मोशन है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, रिकार्ड को देख रहा हूं और डिप्टी चेयरमैन साहब से इस बारे में बातचीत की है। जो लीडरान साहब मुझ से मिलना चाहें वे मुझ से मिल सकते हैं, मगर आज जो काम है वह काम उसी तरीके से चलेगा जिस तरह से वह छपा हुआ है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आज का काम अपनी जगह पर है और जो काम कल शुरू हुआ था और जो खत्म नहीं हुआ वहीं चलना चाहिए क्योंकि वह खत्म नहीं हुआ था ।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Sir, what I want to bring to your notice is that yesterday the entire Opposition, all, it was our unanimous desire and we took it to be so that, after the Home Minister made a statement in reply to the Calling attention Notice, the statement would be taken into consideration and the discussion would proceed. That was our understanding. So it is our unanimous desire and I suppose the majority of the House thinks so. If you take the sense of the House, the majority of the House thinks that it should be taken into consideration on a motion, that the statement which Mr. Chavan made yesterday be taken into consideration. That was moved. The Deputy Chairman did not allow it. So it went on- Before you come to a conclusion, let there be no doubt that the entire opposition irrespective of all shades of opinion, want that that statement be taken into consideration and discussion should proceed.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : When that was the unanimous demand of the entire opposition, the Deputy Chairman who was presiding did not agree to that. Then I made a suggestion that the House may be adjourned and the Chairman may invite leaders of all opposition parties and also the Minister of Parliamentary Affairs, so that they can thrash out, discuss and decide in what manner this should be discussed. But it is unfortunate that you never cared to invite the leaders of the opposition parties and also the Minister of Parliamentary Affairs to discuss this. Without discussing it, without giving any decision on this question, you have put down some other subject for discussion. It is unfair, I should say it is not proper, it is not constitutional either.

MR. CHAIRMAN : No, no.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Yesterday either the matter should have been discussed in the form of a calling attention motion or in the form of a short-duration discussion. But the unanimous demand of the opposition was that it should be discussed on a motion to be moved which was moved yesterday. But even if you do not agree with it, you cannot do away

with the discussion at all. Discussion must take place before any other subject is taken up today. Without that it will be irregular, unconstitutional and illegal. We cannot proceed with the discussion of any other subject without finishing discussion on that.

MR. CHAIRMAN : Discussion I never prevented. Discussion I really allowed. The question was the form of the motion. That was the question. I never prevented discussion, and it is an erroneous impression to say that I did not want discussion.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, this List of Business today which we have got is not in order for the simple reason that there was some unfinished business yesterday. What happens to that? It must find a place in the List of Business today since it was unfinished yesterday. Even according to you the matter was to have been discussed as a short-duration discussion. Even that is not mentioned here. Therefore, it seems that it has been struck out. That is not proper. An unfinished business cannot be struck out. On that ground the order paper is wrong.

Now the suggestion was made yesterday that the matter should be discussed on a consideration motion "that the House takes into consideration" and so on. After that various parties may have their various opinions. As far as the motion is concerned "the House takes into consideration the incidents of such and such date", there it ends. The Congress Party can give their amendment, I can give my amendment, anybody can give his amendment if at all anybody gives an amendment. What is the harm in having a discussion on a consideration motion? I am not suggesting a categorical motion of a particular type. I am suggesting an open, broad motion of that type which allows a discussion. After that the conclusion is to be recorded if at all on the basis of an amendment. Even that is not accepted by you. What we are concerned with is the urgency of the matter, the gravity of the issue. I think, as far as I understand, you know the sentiments of the House. Let us discuss this thing on a consideration motion. After that we shall come to a conclusion according to our different assessment. I do not see why it should not be discussed. Government itself sometimes brings a motion for consideration in the sense that "the House

takes into consid ration such and such thing". Governmc it tself does it. The opposition Members jive amendments and even the Govern n<nt side some times brings amendmc ts Take the case of the President's Address. Government side brings an ai tendment, "having considered it the l ioi.se gratefully thanks the President". I tf ere are some Members who want to tl ank the Government, they can do so. [f I want to disapprove of the police actio and advise Mr. Chavan to take some actii i gaint the authorities and ensure that m<h things should not happen, I can d< so. If somebody wants to condemn the Government as such with one word, I e can do so. Why bar it? I therefoi - think that it is not right to ji t Urike it out of the List of Business i day. In fact it was a carryover. As n h >w we set about the carryover businc your ruling will be final, I realise i . but none the less on the unfinished business yesterday you are requested by us and we plead with you through the D puty Chairman that you give your ru in.; our direction as to how we should sc about it. This is nowhere in the List, oase other thing is coming-

SHRI S. N. MISHRA : Now, Sir, the whole thing kas to be examined in the context of h< implications which have been raised t / certain hon. Members. What are the in plications raised in this connection? Th' one implication yesterday was that duri g the course of a calling attention motion a statement was made by the hon. H me Minister and after that we wanted to get it transformed into a kind of a hort-duiation discussion. That simply cou^l I not be done to the rules. So we were n a jam, there was a kind of stalemate. I ial could not be transformed like tha because a statement was made by l ie Home Minister...

SHRI AKBAL VLI KHAN (Andhra Pradesh) : May I remind you...

SHRI S. N. MISHRA : Do not remind me. ..

SHRI AKBAR ALI KHAN : Cannot I remind you ?

SHRI S. N. MISRA : May I say, Sir, that these re the reasons why we sometimes get \ :ry much excited? We never hold up p(sens like this when they are speaking. Mr. Akbar Ali Khan must have patience. You come after me.

5—22 R.S./70

. SHRI AKBAR ALI KHAN : I am just if minding you...

SHRI S. N. MISHRA : I will have my say all the time. You cannot hold me up. You are trying to be too much sy cophantic.

SHRI AKBAR ALI KHAN : You have no business to say that. But may I remind you...

MR. CHAIRMAN : Please sit down-

SHRI S. N. MISHRA : Why don't you pull him up, Mr. Chairman? He must be pulled up.

MR. CHAIRMAN : I asked him to sit down.

SHRI S. N. MISHRA : After the wrong is done, I must say I must enter a caveat, a warning, that if this kind of thing goes on and the Chair does not give us protection, we will take serious, / drastic action against any person on the other side.

(Interruptions)

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : We do not care for your threat.

SHRI S. N. MISHRA : The Chair has to give me protection. As I was saying, it simply could not be done. The transformation into a short-duration discussion could not take place because the statement had already been made by the hon. Home Minister. That was the technical difficuhy with which we were confronted yesterday. After that stalemate was reached the House was adjourned.

Another thing which has been raised today by the hon. Member, Mr. Raj-narain, is that he was in the midst of his calling attention motion when the House adjourned. The House did not take any decision with regard to the other course to be adopted. So he is right in saying that he is in the midst of his calling attention motion. That being so, what are we to do about it? There has been no pronouncement from the Chair that that thing is being held over. Under the blanket powers enjoyed by the Chair although of course it would not be right to do that under the except powers enjoyed by the Chair—probably that could be held over on a statement from the Chair. But that statement has also not been made. So the hon. Member is quite competent

[Shri S. N. Mishra]

in raising this point that when he was in the midst of his calling attention motion he must be allowed to go on with the calling attention motion. That is number one. If you are going to take more time about the form of discussion that should take place, then the whole question is whether you can do that in the way in which you have sought to do it or whether you can do it only by an appeal to the House that you quite realise the portion that there was a calling attention motion that was continuing. But that position must be made absolutely clear that the Calling Attention Motion is continuing. About that there can be absolutely no doubt.

Then, Sir, the second thing which had happened was that after the hon. Home Minister had his statement, I came up with a formal motion that the statement of the hon. Home Minister be taken into consideration. Now, it is a different matter that I wanted to exert the right of an hon. Member to bring up any motion and to that right, I was sticking with tenacity all the time. But I also wanted to resolve the technical difficulty that has arisen because no discussion could take place unless there was a formal motion on that. That could not be transformed simply into short duration discussion because the statement has already been given. I want to resolve this difficulty simultaneously with my intention to deplore the action of the Government may be later on. But it was a simple, innocent motion made at that time that the statement made by the hon. Home Minister be taken into consideration. Now, I ask you, since yesterday that occupied quite a lot of time of the House, whether the hon. Home Minister should have come out *suo motu* or not with a statement on the sad incident and it was recognised by everybody including the Home Minister that he should come out with a statement *suo motu*. I ask you a definite, clear, categorical question. If that were so, which was the most desirable thing to be done that the hon. Home Minister should have made a statement—how would the discussion have proceeded except in form of a motion for consideration. That motion for consideration could have come from the other side of the House. May be, that motion for consideration might be made by the Home Minister himself. But if that were so, then what is the hitch, What is the difficulty in getting a motion in order to enable us to resolve

this technical deadlock in which we find ourselves at the present moment? Then, with that, there is another question when many of us or rather the whole House said as it was asserted yesterday from the other side of the House also, that the Whole House stands aghast at the incident that had taken place, what is the difficulty in bringing up any motion for consideration of this sad incident which took place on the 6th April? Now, if that is not done, I must say that you would be denying us the right to bring up any motion on a matter of such importance, the importance of which has been recognised by everybody and which has been declared to be very sad, shocking and outrageous by everybody. If you deny us this right, then, you would be denying the House a vital function which it has to perform. And therefore (*Interruption*) No, what I am saying is, why should there be this reticence? It is a unanimous opinion. As the hon. Mr. Rajarain has said if this matter is delayed further, we would be feeling that justice has been denied to us. We are asking for a simple thing, we are making a simple request that you should concede us the right to make a motion with regard to this. And there is nothing to be read into this kind of motion. It resolves the difficulty; at the same time it conforms to the wishes of the majority or, shall I say, even to the unanimous opinion of the House it conforms to the wishes of the whole House, as I see it. Then there should not be any difficulty and we can proceed with it even now. Even now, you can proceed with it, because the business is continuing and there has been no announcement from the Chair that this matter is being held over for some other consideration. That announcement has not been made.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) :
Does the Leader of the House say anything ?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI K. K. SHAH) : I have to say, Sir, that so far as the discussion is concerned, you can permit it any time and I do not want to stand in the way of the discussion. But I do want to point out and I want to beg of the House that there are certain principles laid down which are also defined in the Rules of the Lok Sabha. And I beg of the Leader of the Opposition also because this is the consensus of the House and not of one individual party or individual group. When there is a judicial inquiry, discussion cannot take place
(*Interruptions*)

Please bear with me. Can I not beg of the Leader of the House to extend to me the courtesy to make a submission? I am reading from * 188 of the Lok Sabha—I am not sitting on my own. I am reading what has been defined in detail herein—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved".

SHRI Z. A. A. (Uttar Pradesh): I would like to know why they accepted the Calling Attention Motion.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Chairman, the Leader of the House may make any submission. But is it the contention of the Leader of the House...

SHRI K. K. SHAH : Do not draw your conclusion till you have heard me. Will you kindly hear me and then raise your point of order? I am showing the way. Therefore, kindly hear me. In view of all these difficulties, problems I would request you, Sir, to call the leaders of all the parties into your Chamber between one and two or at two or just now. Healthy traditions have been built up in the past on the other side. I understand the feeling also and let us find out a way which will meet your point of view and which will also save the healthy traditions of the House. Therefore, Sir, I would request that all of them shall be called.

SHRI MAHWIR TYAGI : The Lok Sabha whose Rules you have quoted has already had a discussion on this issue. If has already discussed this.

SHRI K. K. SHAH : At that time no Commission was appointed. Now, the Commission has been appointed already. Even then I say...

SHRI JAIRAM DAS DAULATRAM (Nominated) : The Lok Sabha did not pass any motion.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I would request you not to entertain the argument given by the Leader of the House. If what Mr. Shah has said were to be accepted, then we cannot even raise it as a Calling Attention Motion or half-an-hour discussion, as it might be suggested. After

all, the procedures will be the same, the discussion will be the same, whatever name you will give it.

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : In regard to the riots at Ahmedabad we had a discussion in our House. A Judicial Commission had been appointed at that time. Sir, I raised a point of order but then you ruled it out and the motion was allowed to be discussed, and the discussion did take place in this House. Now, how can you reject this?

SHRI BHUPESH GUPTA : The trouble with the Leader of the House is that he is completely ignorant of what has happened in the past. Mr. Shah means well. But he is completely ignorant of the fact that we have discussed such things on many occasions, and it is not any interference with the administration of justice or the work of the Commission. We are expressing opinions. What opinion will be expressed ultimately in the form of a resolution or amendment, well, we shall see about it later on. But all that we say is that we take into consideration his statement. Government can give a statement. I will have my say. Others will have their say. Having done it, then will come the pronouncement if at all. Therefore, Sir, you need not call us needlessly at this subject. The motion is absolutely non-controversial...

MR. CHAIRMAN : No, no ...

SHRI BHUPESH GUPTA...and it should be considered. The statement should be taken into consideration. Controversy will arise only when the amendment comes. It is a non-controversial motion. The Government should welcome a non-controversial motion. Or do they want a controversial motion?

Here is a Government which does not know how to make selections from its own points. Therefore, Sir, we had been extremely reasonable. We have taken note of the apology by Mr. Chavan. We have not questioned his *bona fides* even. We have taken note of so many things—a Commission has been appointed. When the amendments come we shall keep everything in view. Now face the discussion. Therefore, you kindly go into the matter.

SHRI M. N. KAUL (Nominated) : I have watched the proceedings for the last two days with great care. The matter lies within a narrow compass. So far as

[Shri M. N. Kaul] my recollection goes, when you were presiding in the morning yesterday, there was a clear understanding that there will be a Short Duration discussion. What is involved in a Short Duration discussion is that there will be a discussion and not voting. The proposal that was made after lunch yesterday, was in the form of a motion for consideration where amendments can be moved. The whole object is that there should be voting after the discussion—So there is a sharp division of opinion on that point. The two are quite distinct. The reason, I presume, why you ruled in favour of raising a discussion without voting—let us be quite clear about it—was that the matter was under enquiry with wide terms of reference.

SHRIMATI YASHODA REDDY
(Andhra Pradesh): He never said that.

SHRI M. N. KAUL : No, no. That is my presumption. I am entitled to an expression of my opinion.

MR. CHAIRMAN : Let him be given a fair chance.

SHRI M. N. KAUL :: That was a form appropriate and suited to the present occasion because the matter was under enquiry. The rules do not prohibit Members from expressing their own version of facts, from dilating on the subject at length. What was indicated by your decision was that there will not tie a motion and there will not be voting presumably because the matter was under enquiry and the established facts are not before the House. Some of the facts and the opinions may be established later on. Every Member has expressed regret over what has happened. The administration may be blameworthy. But the appropriate occasion for it will arise when the established facts are before us.

Now, the Leader of the House has cited a rule from the Lok Sabha. It is true that there is no counterpart of that rule in the Rajya Sabha. I was myself responsible for the recommendation and insertion of the rule. The rule was inserted as a form of established Parliamentary procedure. Now it is open to you to follow that rule and adopt it as a matter of Parliamentary practice. It does not invent anything. It merely states the practice for the sake of clarification.

It has been repeatedly said that power belongs to the House. Of course, it belongs to the House. But for the time being under the rules framed by the House you are exercising those powers not personally but as representing the whole House, and you have to weigh the whole thing.

(Interruptions)

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर ।

SHRI M. N. KAUL : Let me have my say. I am not opposed to a conference ...
[Interruptions] Let me proceed. I know that procedure cannot be divorced from politics. The two are mixed up, they are inseparable. Procedure and politics in this case are mixed up. The entire Opposition is united on one procedure. Now the question is...

SHRI RAJNARAIN : On a point of order :
...

SHRI M. N. KAUL .. Let there be a conference to thrash out the matter. I do not know whether it is possible to devise an agreed motion. But we should try, as far as possible, to meet the wishes of the Opposition and devise a form of words to which you, Sir, will be agreeable, and it will meet the ends of the case.

श्री सभापति : श्री राजनारायण ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप खुद ही सोचें कि प्वाइंट आफ आर्डर पर हमको बुला कर के अब क्या करेंगे ।

श्री सभापति : उस वक्त वह बोल रहे थे, वह बैठे नहीं ।

श्री राजनारायण : आप खुद सोचें कि आप हमारे लिये ही सक्षम हैं या कौल साहब ऐसे व्यक्ति के लिये भी सक्षम हैं । हम तो खुद ही इस समय असक्षम हैं ।

श्री सभापति : आप बोलिये भी ।

श्री राजनारायण : हमारा प्वाइंट आफ आर्डर उन्होंने खत्म ही कर दिया । मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री कौल साहब एक नामिनेटेड मेम्बर हैं, वह पालिटिक्स को डिफेम करने की कोशिश बार बार इस सदन में न किया करें । पालिटिक्स को डिफेम किया उन्होंने । मैं आपसे

यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सदन में, इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज है जो कि पालिटिक्स से अछूती हो। एक नानसेंसिकल टाक करना है कि पालिटिक्स को ले कर के कोई काम नहीं होता।

श्री महेश्वर नाथ कौल : मैंने कहा कि इनसेपेरेबिल है, प्रोसीजर एंड पालिटिक्स इनसेपेरेबिल है। आप मेरे लफ्जों को तोड़-मोड़ कर बात न करिये।

श्री सभापति : आपको प्वाइंट आफ आर्डर पर क्या कहना है ?

श्री राजनारायण : मेरे प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अब आप क्यों इस डिस्कशन को ज्यादा बढ़ा रहे हो। मैं समझता था कि कौल साहब जब बोलेंगे तो जो इसका गूढ़ तत्व है उसको पकड़ कर के बोलेंगे क्योंकि इतने दिनों तक वह लोक सभा के सेक्रेटरी रहे हैं। मैं असमर्थ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि मैं आपको अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ। आज आपको सामने केवल दो ही विकल्प हैं और इसी पर आपको फैसला लेना है कि आया हमारा कल का प्रस्ताव काँग्रेस अटेंशन के रूप में आज चलेगा या वह डिस्कशन के रूप में चलेगा। यही फैसला होने के लिये कल सदन आज के लिये उठा। इसी पर आपको अपनी आज व्यवस्था देनी है। नेता सदन न मालूम कहां इधर से उधर चले गये। नेता सदन, नेता सदन, नेता सदन, इधर बैठिये।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : जरा मुन लीजिये।

श्री सभापति : अब कहां तक मुनें।

श्री राजनारायण : हमारे साथ कितना अन्याय होगा आप समझ नहीं पाते। मैं कहना चाहता हूँ कि शुद्ध संसदीय प्रथा चलानी है तो उसको शुद्ध बुद्धि से भी चलानी होगी। आज आपने अखबारों को पढ़ा है, दिल्ली से जितने भी अखबार निकल रहे हैं बाहर के लोग दिल्ली के अखबारों को पढ़ कर क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि कल सदन में क्या घटना घटी।

मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेक्रेटैरियट को यह आदेश करें, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, कि इस सदन में जो बातें हो उसका सही प्रतिनिधित्व हो। मुनिये, एक अखबार ने लिखा : राजनारायण व्हील चेयर में लोक सभा में ले जाये गये। यह फ्रंट पेज पर है। आपके सेक्रेटैरियट को उसको क्वेश्चन करने का, उसका खंडन करने का, कोई महत्व नहीं मालूम होता है। पढ़ लीजिये आप।

श्री सभापति : अच्छा, अब बैठिये।

श्री राजनारायण : मुनिये एक मिनट। एक अखबार ने यह लिखा है कि राजनारायण चमकीली छड़ी ले कर चले। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह दुखदायी छड़ी है। यह दुखदायी छड़ी है, चमकीली छड़ी नहीं है और यह अस्पताल ने बनाके हमको दी है हमारी यह छड़ी नहीं है, यह अस्पताल ने बना कर के दी है।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये राजनारायण जी।

श्री राजनारायण : क्या आप चाहते हैं कि यह व्यवस्था है, आप चाहते हैं कि क्या आज बहस न हो। बहस न हो और तमाम अखबारों से गलत बर्ज़न जाये...

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये।

श्री शेड० ए० अहमद : जनाब, अब आप हाउस को एडजर्न करें और चैम्बर में बुलायें।

श्री राजनारायण : ...और जो समाचारपत्रों के द्वारा इनका सूचना विभाग गलत खबर छपवा रहा है उसके बारे में हम अपनी बात न कहें। इसलिये मैं चाहता हूँ...

श्री सभापति : अच्छा, अब आप बैठिये।

(Interruption)

No more. I adjourn the House up to 2 o'clock and I request the leaders of the various groups to see me in the Chamber just now.

The House then adjourned at fifty minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the Clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ANNOUNCEMENT *RE* CALLING ATTENTION NOTICE ADMITTED FOR TUESDAY, THE 28TH APRIL, 1970

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Calling Attention Notice which was fixed today for regarding the growing Naxalite activities in West Bengal, etc. will be taken up tomorrow.

Now we proceed with Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE HINDUSTAN INSECTICIDES LIMITED, NEW DELHI TOGETHER WITH THE AUDITORS' REPORT ON THE ACCOUNTS

II. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE HINDUSTAN ANTI BIOTICS LIMITED, PIMPRI, TOGETHER WITH THE AUDITORS' REPORT ON THE ACCOUNTS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, on behalf of Shri D. R. Chavan, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each of the following papers:

- (a) (i) Fifteenth Annual Report and Account of the Hindustan Insecticides Limited, New Delhi, for the year 1968-69 together with the Auditors' Report on the Accounts.
- (ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. See No. LT-3314/70 for (i) and (ii)]

- (b) (i) Fifteenth Annual Report and Accounts of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, for the year 1968-69 together with the Auditors' Report on the Accounts.

- (ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. See No. LT-3314/70 for (i) and (ii)]

REPORT OF THE INDIAN DELEGATION TO THE 22ND WORLD HEALTH ASSEMBLY

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Indian Delegation to the 22nd World Health Assembly held at Boston, Massachusetts, U. S. A. from July 8 to 25-1970. [Placed in Library. See No. LT-3368/70]

THE INCOME-TAX (SIXTH AMENDMENT) RULES, 1969

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. RAGHURAMAIAH) : Sir, on behalf of Shri P. C. Sethi, I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification S. O. No. 5056, dated the 29th December, 1969 (in English and Hindi), publishing the Income tax (Sixth Amendment) (Rules, 1969, under section 296 of the Income Tax Act, 1961. [Placed in Library. See No. LT-3315/70]-

NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE)

SHRI K. RAGHURAMAIAH ; Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance)

- (i) Notification G. S. R. No-515, dated the 25th March 1970, together with an Explanatory Memorandum thereon-
- (ii) Notifications G. S. R. No 516 and 517, dated the 26th March, 1970, together with Explanatory Memoranda thereon

[Placed in Library. See No. LT-3231/70 for (i) and (ii)]

- (iii) Notifications G. S. R. Nos. 583 and 584, dated the 1st April, 1970, together with an Explanatory Memorandum thereon-

- (iv) Notifications G. S. R. Nos. 572, 574 and 575, dated the 4th April 1970, together with Explanatory Memorandum thereon.

[Placed in Library. See No. LT-3232/70 for (iii) and (iv)]